साप्ताहिक
जागत गांव हमार
पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक
RNI-MPHIN/2015/72544
चौपाल से भोपाल तक
भोपाल, सोमवार, 19-25 फरवरी 2024 वर्ष-9, अंक-44
भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित
पृष्ठः-8,मूल्यः- 2 रुपए

» प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि

» बारिश से गेहूं को होगा फायदा, लेकिन दलहन को नुकसान

» प्रदेश में बेमौसम बारिश पर कृषि वैज्ञानिकों ने किया दावा

» जबलपुर जिला प्रशासन ने किया गांवों का निरीक्षण

प्रदेश में मौसम की मारः सरकार ने कहा-किसानों को प्रभावित फसलों का मिलेगा मुआवजा

मप्र में बारिश के साथ गिरे ओले किसानों की फसल हुई बर्बाद

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश के कई जिलों में मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है। इतना ही प्रदेश के डेढ़ दर्जन से ज्यादा जिलों में ओले भी जमकर गिरे हैं। जबलपुर में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। जिसकी वजह से किसानों की फैसलें बर्बाद हो गई है। ऐसा ही हाल मंडला जिले में भी देखने मिला।

जहां ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। इसी तरह मऊगंज, रीवा, सीधी-शहडोल जिले में भी बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। जबलपुर के बरगी विधानसभा क्षेत्र के कुछ गांव में इतने अधिक ओले गिरे की कच्चे मकान के छत टूट गए और उनके घरों के भीतर ओले आ गए। वहीं किसानों की फैसले भी बर्बाद हो गई है। यह रबी सीजन की फसलों के पनपने का समय है। इस दौरान खेतों में गेहूं, चना, मसूर, बटरी, सरसों, जौ जैसी फैसलें लगभग तैयार हो चुकी हैं। इस ओलावृष्टि की वजह से इन फसलों को भारी नुकसान हो गया है।

मुआवजा मिलेगा वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार छतरपुर जिले के चांदला विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में पहुंचे, जहां ओलावृष्टि से किसानों की फसल खराब हुई है। राज्यमंत्री ने स्वयं खेतों में जाकर खराब हुई फसलों का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार उनकी चिंता करेगी। राज्यमंत्री ने कहा कि ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाया जाएगा।

डिंडोरी-मंडला में फसल चौपट

डिंडोरी जिले के शहपुरा विकासखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में ओलों की आफत देखने को मिली। यहां ओलों की जमकर बरसात हुई। ओले गिरने से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। भारी बारिश व ओलावृष्टि से चना, मटर, सरसों, गेहूं आदि फसलों को नुकसान पहुंचा है। वहीं मंडला में तेज बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान का विधायक चैन सिंह वरकड़े ने निरीक्षण किया। उनके साथ तहसीलदार शंकर लाल मरावी व अन्य अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया है।

मदद और सर्वे की गुहार

इधर, किसान और किसान संगठनों ने तत्काल प्रशासन से मदद और सर्वे की गुहार लगाई, जिसके बाद प्रशासनिक और कृषि विभाग से जुड़े अधिकारियों को गांव का दौरा शुरू कर दिया है। सर्वे के दौरान कई जिलों में ओलावृष्टि होने की बात सामने आई, जिसके बाद वैज्ञानिकों और कृषि विभाग के साथ बैठक कर अगला कदम उठाया जाएगा।

- बारिश और ओलावृष्टि के बाद प्रशासनिक अधिकारियों को इससे हुए नुकसान का जायजा लेने भेजा गया था। अब तक की जानकारी में 20 से ज्यादा गांव में चने के आकार के ओले गिरे हैं। इससे कितना नुकसान हुआ है, इसका भी पता लगाया जा रहा है। किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सर्वे के बाद नियमानुसार राहत राशि दी जाएगी।
दीपक सक्सेना, कलेक्टर, जबलपुर
- इस बारिश और ओलावृष्टि से उन फसलों को ज्यादा नकसान पहुंचा है, जिसमें फूल आ रहे थे। वहीं अलसी समेत दलहन फसलों को भी नुकसान हुआ, लेकिन हां, इससे गेहूं को फायदा हुआ है। जबलपुर में बरगी, जबलपुर, शहपुरा, पाटन, पनागर, कटंगी तहसीलों में फसलों को ज्यादा नुकसान हुआ।
डॉ. दिनकर शर्मा, डायरेक्टर, जवाहरलाल नेहरू कृषि विवि, एक्सटेंशन विभाग
- ओलावृष्टि व अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। तेज पानी हवा के कारण गेहूं की फसलें खेतों में बिछ गई हैं। ओलावृष्टि व अतिवृष्टि के कारण किसानों की चना, मसूर, मटर को भारी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन से मांग है कि तत्काल फसलों की क्षति का सर्वे करने का निर्देश जारी करें।
राघवेंद्र सिंह पटेल, भारतीय किसान संघ के अभा प्रचार प्रमुख

सीएम डॉ. मोहन यादव ने दी अधिकारियों को दी बधाई

ग्रामीण पर्यटन परियोजना के लिए मप्र को सिल्वर अवॉर्ड

भोपाल। जागत गांव महार

मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को नई दिल्ली में 96वीं स्कॉच समिट में ग्रामीण पर्यटन परियोजना के लिए टूरिज्म श्रेणी में सिल्वर अवॉर्ड से नवाजा गया है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित हुए एक समारोह में पर्यटन बोर्ड की ओर से संचालक मनोज सिंह ने पुरस्कार ग्रहण किया। ग्रामीण पर्यटन परियोजना अंतर्गत मध्य प्रदेश के छह संस्कृति क्षेत्र में सौ गांव चयनित किए गए थे, जिसमें 30 गांवों में परियोजना के तहत कार्य शुरू हो चुका है और विदेशी पर्यटक भी यहां पहुंचना शुरू हो गए हैं। साथ ही देशी पर्यटकों ने भी परियोजना में रुचि दिखाई है।

सीएम मोहन यादव ने दी

मप्र पर्यटन विभाग की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बधाई दी है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर कहा कि मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को नई दिल्ली में आयोजित 96वीं स्कॉच समिट में ग्रामीण पर्यटन परियोजना के लिए टूरिज्म श्रेणी में सिल्वर अवॉर्ड से सम्मानित होने पर पर्यटन विभाग की पूरी टीम को बधाई। यह सम्मान पूरे विभाग के समर्पण का प्रतिफल है। यह पुरस्कार न सिर्फ मध्यप्रदेश के ग्रामीण पर्यटन को और अधिक बढ़ावा देगा, बल्कि इससे रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

योजना पर एक नजर मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा वर्ष 2019 में ग्रामीण पर्यटन परियोजना की शुरुआत की गई थी। केंद्र सरकार ने भी इस परियोजना महत्व दिया है और अन्य राज्यों में भी ग्रामीण परियोजना की शुरुआत हो चुकी है। परियोजना के तहत स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिला है।

लाइसेंस पर कारोबारी मंडी उपज खरीदी नहीं कर सकता

मप्र में अब मंडी लाइसेंस 30 साल तक के लिए बनेंगे

अभी हर पांच साल में लाइसेंस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश के मंडी कारोबारियों के लिए सुकून वाली खबर है कि अब मंडी लाइसेंस की समयावधि 30 साल रहेगी। लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को आनलाइन कर दिया गया है। वाणिज्य सव्यवहार लाइसेंस फीस में राहत प्रदान करते हुए 25 हजार रुपये से कम कर 5 हजार रुपए कर दिए हैं। मध्य प्रदेश राज्य कृषि मंडी बोर्ड ने अधिनियम में संशोधन कर कृषि मंडियों में व्यापार करने के लिए लाइसेंस फीस 5 हजार रुपए व आवेदन शुल्क 100 रुपए निर्धारित था। इसमें आवेदन शुल्क को 200 रुपए कर दिया है। लाइसेंस फीस यथावत रखी गई है। लाइसेंस की समयावधि 30 साल कर दी है। वाणिज्य संव्यवहार के लिए बनने वाले लाइसेंस के लिए अब तक 25 हजार रुपए फीस थी, जिसे कम कर 5000 रुपए कर दिया है। इस लाइसेंस पर कारोबारी मंडी नीलामी में उपज खरीदी नहीं कर सकता, लेकिन व्यापारी से व्यापारी खरीदी कर सकेंगे।

» कारोबारियों के लिए लाइसेंस लेने पर फीस में भी राहत दी

» लाइसेंस फीस पहले 25 हजार थी, अब 5000 रुपए कर दिया

सुविधा लाभदायक

व्यापारी से व्यापारी कारोबार करने के लिए लाइसेंस लेने पर फीस में भी राहत प्रदान की है। उक्त मांगें मध्य प्रदेश मंडी व्यापारी महासंघ द्वारा लंबे अरसे से की जा रही थी। महासंघ अध्यक्ष गोपालदास अग्रवाल ने इस सुविधा को व्यापारियों के लिए लाभदायक बताया।

- अब कृषि मंडियों में कारोबार करने के लिए लाइसेंस प्रक्रिया में काफी सरलीकरण दिया गया है। अभी तक कारोबारियों को हर पांच साल में लाइसेंस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। अब 30 साल बाद नवीनीकरण करवाना होगा।
श्रीमन शुक्ल, प्रबंध संचालक

लेखानुदानः मोहन सरकार ने एक ही झटके में सबको साधा

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में डॉ. मोहन यादव की सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 1,45, 229 करोड़ रुपए का पहला अंतरिम बजट यानी लेखानुदान पेश किया। भाजना के मिशन 370 को केंद्र में रखकर तैयार किए गए इस अंतरिम बजट मे मोदी की गारंटी और विकसित मध्य प्रदेश की झलक दिखाई दे रही है, जिसमें समाज के सभी वर्गों के विकास और कल्याण के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र को अमलीजामा पहनाने का प्रयास किया गया है। मोदी की चार जाति-गरीब, महिला, किसान और युवा वर्ग के कल्याण पर फोकस किया गया है। कर्मचारियों और पेंशनर के लिए चार प्रतिशत डीए और महंगाई राहत का प्रावधान किया गया है। वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में अंतरिम बजट पेश किया।

किसानों पर धनवर्षा

» 2024-25 में 442 करोड़ रुपए राजस्व आधिक्य अनुमानित

» सरकार अधोसंरचना विकास पर 59 हजार 342 करोड़ व्यय करेगी

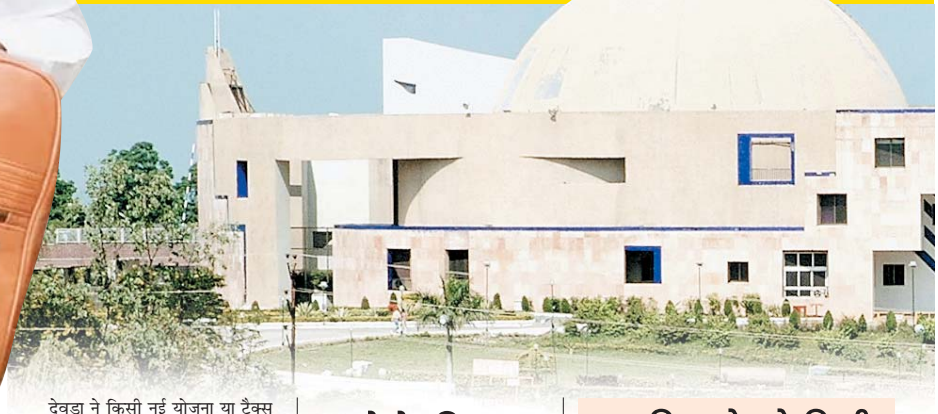

देवड़ा ने किसी नई योजना या टैक्स की घोषणा नहीं की है। यह अंतरिम बजट चार महीने के लिए लागू रहेगा। उप मुख्यमंत्री ने पटल पर वर्ष 2024-25 के लिए लेखानुदान पेश किया। मोहन सरकार लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में पूर्ण बजट पेश करेगी। एक अप्रैल से 31 जुलाई तक के लिए महिलाओं की लाड़ली बहना और अन्य योजनाओं के लिए 9438 करोड़ का प्रावधान किया गया है। किसानों को ब्याज रहित ऋण देने और स्थाई विद्युत पंप पर अनुदान देने के लिए कृषक मित्र योजना को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाने के लिए 9588 करोड़ किसान कल्याण विभाग को दिए गए हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए दुग्ध उत्पादन पर प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। किसानों को बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध कराने के लिए सहकारिता विभाग को 443 करोड़ दिए जाएंगे। संकल्प पत्र 2023 कर गारंटी को पूरा करते हुए किसानों की आय बढ़ाने के लिए मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहित करने दुर्गावती श्री अन्न योजना लागू की जा रही है। इसमें किसानों को प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

गांवों के विकास पर पूरा फोकस

नई योजना तो इसमें कोई शामिल नहीं की गई पर यह अवश्य साफ कर दिया कि सरकार की प्राथमिकता में महिला, किसान, अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़ा वर्ग के साथ शहर और गांवों का विकास करना है। अधोसंरचना विकास को गति वैसी जारी रखी जाएगी, जैसी डबल इंजन की सरकार में चल रही है। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए तीन लाख 48 हजार 986 करोड़ का बजट अनुमान है। केंद्रीय करों में हिस्सा, केंद्रीय सहायता सहित अन्य माध्यमों से कुल दो लाख 52 हजार 268 करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा। इसमें राज्य कर से 96 हजार 553 करोड़ की आय होगी।

इन विभागों को मिली इतने करोड़ की राशि

दो लाख 51 हजार 825 करोड़ व्यय का अनुमान लगाया है। वर्ष 2024-25 में 442 करोड़ राजस्व आधिक्य अनुमानित है। वहीं, सरकार अधोसंरचना विकास पर आगामी वित्तीय वर्ष में 59 हजार 342 करोड़ व्यय करेगी। यह वर्ष 2023-24 में 56 हजार करोड़ निर्धारित की गई है। मोहन सरकार ने अंतरिम बजट में किसानों के लिए ऊर्जा, पशुपालन, उद्यानिकी, सहकारिता, जल संसाधन, नर्मदा घाटी सहित अन्य विभागों को आवश्यकता के अनुरूप राशि उपलब्ध कराई है। ऊर्जा विभाग के लिए सात हजार 963 करोड़ का प्रावधान रखा है।

अंतरिम बजट में किसे क्या मिला

» कोई नया कर नहीं, जुलाई में आएगा बजट, 3,48,986 करोड़ का होगा

» चार महीने के खर्च के लिए 1,45,229 करोड़ का अंतरिम बजट प्रस्तुत

» सड़क, एक्सप्रेस वे सहित अधोसंरचना विकास को गति मिलेगी

» कर्मचारी और पेंशनर्श को चार प्रतिशत डीए और महंगाई राहत

» दुग्ध उत्पादक किसानों को प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि

» किसानों को विद्युत पंप के लिए अनुदान दिया जाएगा

» अजजा के लिए जनसंख्या के अनुपात में 23 फीसदी बजट

» अजा कल्याण के लिए जनसंख्या के अनुरूप 16 फीसदी राशि

» पर्यटन स्थलों तक हवाई सुविधाएं विकसित करने हेली टूरिज्म

» आपातकालीन परिस्थितयों के लिए एयर एंबूलेंस सुविधा मिलेगी

» मप्र के सभी 55 जिलों में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज

» 1845 शैक्षणिक पद और 387 प्रशासनिक पद भी स्वीकृत

» पीएम जनमन योजना में जनजातियों के लिए बढ़ेंगी सुविधाएं

जना पर न कोई टैक्स लगाया न ही कोई योजना बंद होगी

मोदी की गारंटी पर काम

मध्यप्रदेश सरकार मोदी की गारंटी पर काम कर रही है। चार महीने तक सभी योजनाएं चलती रहें, इसके लेखानुदान लाया गया है। सभी योजनाएं यथावत चलती रहेंगी। नई योजना शुरू नहीं की जाएगी। लेखानुदान या अंतरिम बजट के माध्यम से विभागों को अप्रैल से जुलाई 2024 तक विभिन्न योजनाओं में राशि व्यय करने के लिए आवंटित की गई है। सरकार लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में पूर्ण बजट प्रस्तुत करेगी।

जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री

घोषणाएं पूरी नहीं हो रहीं

मोदी की गारंटी पूरी नहीं हो रही है। जमीन पर कुछ बदलाव दिखे, तब तो हम मानेंगे कि मोदी गारंटी पूरी हो रही है। घोषणाएं पूरी होती नजर नहीं आ रही हैं। जब 2023-24 का 58 फीसदी बजट ही खर्च हुआ है 42 प्रतिशत बजट बकाया है तो मप्र के ऊपर नया कर्ज क्यों लादना चाह रही है। हम इस लेखानुदान का समर्थन नहीं कर सकते।

उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष

» कर्मचारियों और पेंशनर के लिए चार फीसदी महंगाई राहत

» सरकार ने पेश किया 1,45,229 करोड़ का पहला अंतरिम बजट

» बजट में मोदी की गारंटी और विकसित भारत के मध्य प्रदेश की झलक

» 2024 को साधने गरीब, महिला, किसान, कर्मचारी, युवाओं पर फोकस

» अप्रैल से 31 जुलाई तक खर्च और योजनाओं के लिए धन का प्रावधान

» वित्त मंत्री ने पेश किया लेखानुदान, करारोपण संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं

» सरकार लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में पूर्ण बजट पेश करेगी

» एक लाख 45 हजार करोड़ रुपए का लेखानुदान पेश किया गया

सिंचाई सुविधाओं का होगा विस्तार

ऊर्जा विभाग अटल कृषि ज्योति योजना के माध्यम से सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए बिजली कंपनियों को अनुदान देता है। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रदेश में कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए केंद्रीय बजट में साढ़े तीन हजार करोड़ का प्रावधान रखा है। इसके लिए राज्यांश जल संसाधन ने रखा है। विभाग को तीन हजार 74 करोड़ और नर्मदा घाटी विकास एक हजार 529 रुपए आवंटित किए गए हैं।

मोहन सरकार की प्राथमिकता में महिला

सरकार की प्राथमिकता में महिला प्रारंभ से ही रही है। लाड़ली लक्ष्मी योजना हो या फिर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह (कन्यादान-निकाह) या फिर बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति वर्ग की महिलाओं को आहार अनुदान या फिर लाडली बहना योजना, सबके लिए बजट में राशि रखी गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग को चार माह के लिए 9,438 करोड़ मिलेंगे। स्वास्थ्य, जनजातीय कार्य, अनुसूचित जाति कल्याण सहित अन्य विभागों के बजट में भी महिलाओं के लिए राशि निर्धारित की गई है।

चार नए ग्लोबल स्किल पार्क

चार नए ग्लोबल स्किल पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। फ्यूचर जॉब स्किल पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए जबलपुर, उज्जैन, भोपाल का चयन किया गया है। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला में भाग लेने पर सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग को राशि उपलब्ध कराई जा रही है।

एयर एंबुलेंस सेवा

सड़क, औद्योगिक कारिडोर निर्माण और एक्सप्रेस वे को गति देने के लिए पीडब्ल्यूडी को 4098 करोड़ दिए गए हैं। स्वस्थ मध्य प्रदेश की परिकल्पना को साकार करने के लिए एयर एंबुलेंस सेवा आरंभ की जाएगी। युवा वर्ग को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पीएम एक्सीलेंस कॉलेज का निर्माण सभी जिलों में किया जाएगा।

सात लाख आवास का लक्ष्य 450 में मिलती रहेगी गैस

खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग को लाड़ली बहनों को 450 रुपए में रसोई गैस उपलब्ध कराने के लिए राशि निर्धारित की गई है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को मुख्यधारा में लाने के लिए एक साथ कई मोर्चों पर सरकार काम कर रही है। सामाजिक न्याय विभाग को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए राशि दी गई है तो प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण में सात लाख आवासों को पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सहायता के लिए श्रम विभाग को राशि दी जा रही है। केंद्र और राज्य के प्रयासों के चलते नौ वर्षों में प्रदेश के दो करोड़ 30 लाख लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं।

हेलीकाप्टर भी उड़ेगा

केरल की तरह पर्यटन क्षेत्र से रोजगार की संभावनाएं बढ़ाने के लिए पांच पर्यटन केंद्रों तक हेलीकाप्टर चलाने की तैयारी सरकार ने अंतरिम बजट में की है। आदिवासी विकास के पीएम मोदी के सपने को साकार करने के लिए 23 जिलों में पीएम जनमन योजना को जमीन पर उतारने के लिए अनुसूचित जनजाति कल्याण के बजट में 7500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

बढ़ेगी स्कूलों की संख्या

गरीब परिवार की महिलाओं को गर्भावस्था और प्रसव के दौरान मिलने वाली प्रसूति सहायता योजना के लिए 200 करोड़ की व्यवस्था की गई है। श्रमिकों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालयों की संख्या बढ़ाई जाएगी।

अनुमान में आय और खर्च

» राजस्व प्राप्तियां 2,52,268.03 करोड़

» कर से राजस्व प्राप्तियां 96,553.30 करोड़

» गैर कर राजस्व प्राप्तियां 18,077.33 करोड़

» राजस्व व्यय 2,51,825.13 करोड़

» पुनरीक्षित अनुमान में राजस्व व्यय 2,31, 112.34 करोड़

» बजट अनुमान में राजस्व आधिक्य 442.90 करोड़

» पूंजीगत प्राप्तियां का बजट अनुमान 59,718.64 करोड़

» पूंजीगत परिव्यय का बजट अनुमान 59,342.48 करोड़

» बजट में सम्मिलित राशि 3,48,986,57 करोड़

» लेखानुदान के लिए धनराशि 1,45,229,55 करोड़

» लेखानुदान राशि में मतदेय 1,19,453.05 करोड़

विभागवार राशि का आवंटन

विभाग	राशि
कृषि विभाग	9588 करोड़
महिला बाल विकास	9360 करोड़
उच्च शिक्षा विभाग	1240 करोड़
पंचायत विभाग	4228 करोड़
जनसंपर्क विभाग	289 करोड़
ग्रामीण विकास	5100 करोड़
नगरीय विकास	4654 करोड़
स्कूल शिक्षा विभाग	11674 करोड़
स्वास्थ्य विभाग	5417 करोड़
चिकित्सा शिक्षा	1228 करोड़
सहकारिता विभाग	443 करोड़
ऊर्जा विभाग	4059 करोड़
गृह विभाग	4274 करोड़
आदि.ज.विभाग	4287 करोड़
अजा विभाग	787 करोड़
लोक निर्माण विभाग	3132 करोड़
श्रम विभाग	391 करोड़
सामाजिक न्याय	1820 करोड़
ओबीसी के लिए	514 करोड़

विश्व के 65 देशों में किसान कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन, जानिए क्यों

किसानों के विरोध के स्वर सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया से उठे हैं। जनवरी 2023 से देखें तो दक्षिण अमेरिका के 67 फीसदी देशों में किसानों ने कई वजहों से विरोध प्रदर्शन किए। इनमें बेहतर निर्यात विनिमय दरों से लेकर करों में कमी करने की मांगें तक शामिल रही। गौरतलब है कि यह मांग उस समय उठी है जब अर्थव्यवस्था जूझ रही थी और अर्जेंटीना में भीषण सूखा पड़ा था। अर्जेंटीना में सूखे से फसलों को नुकसान पहुंचा और किसानों के लिए हालात बद से बदतर हो गए थे। ब्राजील में, किसानों ने इसलिए विरोध किया क्योंकि उन्हें लगा कि आनुवंशिक रूप से संशोधित मक्का कृषि बाजारों में अनुचित प्रतिस्पर्धा पैदा कर रहा है।

वेनेजुएला में, किसानों ने सस्ते डीजल को लेकर अपनी मांग सरकार के सामने रखी। कोलम्बिया में, धान किसानों ने अपनी फसल की अच्छी कीमतों को लेकर प्रदर्शन किए थे।

इस दौरान यूरोप के करीब 47 फीसदी देशों में किसान प्रदर्शन के लिए मजबूर हुए हैं। इनके पीछे फसल की उचित कीमतों का न मिलना, बढ़ती लागतें, कम लागत वाले आयात और यूरोपियन यूनियन द्वारा जारी पर्यावरण नियम जैसे कारण जिम्मेवार रहे। उदाहरण के लिए, फ्रांस के किसानों ने सड़कों पर उतरकर कम लागत वाले आयात, सब्सिडी की कमी और उत्पादन की भारी लागत को लेकर विरोध प्रदर्शन किए।

ऐसा ही कुछ उत्तर और मध्य अमेरिकी देशों में भी देखने को मिला, जहां 35 फीसदी देशों में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किए थे। जहां मेक्सिको में, किसान अपने मक्के और गेहूं की कम कीमतों को लेकर नाखुश थे। वहीं कोस्टा रिका में, उन्होंने सरकार से मदद की मांग की है क्योंकि उनका आरोप है कि उद्योग कर्ज से जूझ रहा है। इसी तरह सितंबर 2023 में, चिहुआहुआ के सूखाग्रस्त क्षेत्र में मैक्सिकन किसानों ने विरोध किया था क्योंकि वे निर्यात के लिए अमेरिका को सीमित पानी का निर्यात करने के अपनी सरकार के फैसले से खुश नहीं थे।

इस दौरान अफ्रीका के करीब 22 फीसदी देश किसानों के विरोध प्रदर्शन के गवाह रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से इसलिए हुए क्योंकि किसानों को उनकी फसलों के अच्छे दाम नहीं मिल रहे थे और उनकी लागत बहुत अधिक थी।

उदाहरण के लिए, अगस्त 2023 में केन्या के आलू किसानों ने अपनी फसल की उचित कीमत पाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया था। वहीं बेनिन में, कोको किसान परेशान थे क्योंकि उनसे उनकी जमीनें छीनी जा रही थी या उनके कोको फार्म नष्ट किए जा रहे थे। वो अपनी जमीनों को विदेशी कंपनियों को बेचे जाने के भी खिलाफ थे।

इसी तरह कैमरून में, किसान नाइजीरिया को कोको का निर्यात बंद करने के सरकारी फैसले के खिलाफ थे। केन्या में, कॉफी किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया क्योंकि कई निजी कॉफी मिलें बंद हो गईं थी और उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। केन्या में गन्ना और चाय किसानों ने भी अनुचित सरकारी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई थी। वहीं नाइजीरिया की महिला किसान ने देश भर में खेती के दौरान आने वाली चुनौतियों पर आवाज बुलंद करने के लिए सड़कों पर उतर आई थी।

एशिया के भी करीब 21 फीसदी देशों में किसानों द्वारा किए विरोध प्रदर्शन की घटनाएं सामने आई हैं। इसमें भारत के कम से कम नौ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किसानों द्वारा किए विरोध प्रदर्शन शामिल हैं।

ऐसी ही एक घटना 13 फरवरी, 2024 को हुई थी जब देश भर के किसान फसलों की कीमतों, किसानों की आय दोगुनी करने और ऋण माफी जैसी मांगों को लेकर दिल्ली में एकत्र हुए थे। नेपाल में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया था क्योंकि उन्हें भारत से आयात की जा रही सब्जियों के उचित दाम नहीं मिल रहे थे। इसी तरह मलेशिया और नेपाल में, क्रमशः चावल और गन्ने की कम कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए थे।

किसानों के विरोध प्रदर्शन की कुछ घटनाएं ओशिनिया में भी सामने आई थी। जहां दो देशों (14 फीसदी) में यह विरोध प्रदर्शन दर्ज किए गए। गौरतलब है कि जहां 2023 में न्यूजीलैंड के किसानों ने उन पर और अन्य खाद्य उत्पादकों पर लगाए सरकारी नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं ऑस्ट्रेलिया में, किसानों ने प्रस्तावित हाई-वोल्टेज ओवरहेड पावरलाइनों का विरोध किया जो उनकी जमीन से होकर गुजरेंगी।

साभार

टिकाऊ खेती आधुनिक समय की मांग और आवश्यकता

» मौहम्मद हसनैन
» श्रीपति द्विवेदी
» दिग्विजय सिंह
» फिरोज सैफी
» राजीव कुमार सिंह
वैज्ञानिक, भाकृअनुप-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, पूसा, समस्तीपुर, बिहार। शोध छात्रा, डा. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विवि, पूसा, समस्तीपुर, बिहार। कृषि छात्रा, अमर सिंह डिग्री कॉलेज बुलंदशहर, उप्र। प्रधान वैज्ञानिक, भाकृअनुप-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली

कृषि, भारत की लगभग 58 प्रतिशत जनसंख्या को आजीविका प्रदान करती है तथा देश की खाद्य सुरक्षा को भी सुनिश्चित करती है। देश के किसान, कृषि वैज्ञानिक शोध एवं विकसित आधुनिक अनुसंधान और तकनीकी का उपयोग कर उत्पादन में लगातार वृद्धि कर रहे हैं। इसके साथ ही आधुनिक तकनीकी के कुछ दुष्प्रभाव भी उत्पन्न हुए हैं, जैसे कि प्राकृतिक संसाधनों, विशेष रूप से मृदा व जल का अतिदोहन हुआ है। इस दोहन से कृषि में कई चुनौतियां भी उत्पन्न हुई हैं। इनका समाधान ही टिकाऊ/स्थायी/सतत खेती के रूप में भी उभरकर सामने आया है।

आधुनिक अनुसंधान और तकनीकी के कारण कृषि उत्पादन में निरंतर वृद्धि तो हो रही है, साथ ही इसके अनेक नुकसान भी सामने आएं हैं। भूजल का गिरता हुआ स्तर, मृदा से कार्बनिक पदार्थ समाप्त होने का खतरा, जलवायु परिवर्तन की व्यापक चिंता, मानसूनी वर्षा की अनिश्चितता और तापमान में वृद्धि जैसी समस्याएं वर्तमान कृषि में अस्थिरता उत्पन्न कर रही हैं।

मृदा जैविक कार्बन: मृदा में उपस्थित जैविक कार्बन कृषि के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण है। मध्यम वर्ग की उपजाऊ मृदा में जैविक कार्ब न 0.4-0.75 प्रतिशत होने चाहिए। किसान फसलों के लिये यूरिया या डाइ-अमोनियम फॉस्पेफट का उपयोग करते हैं। इन रासायनिक उर्वरकों से नाइट्रोजन और फॉस्पफोरस को फसलों के लिये उपयोगी बनाया जाता है। इसके लिए मृदा में उपयुक्त जैविक कार्बन स्तर का होना अत्यंत आवश्यक है। कार्बनिक पदार्थ सूक्ष्मजीवों के आहार के स्रोत भी हैं। ये सूक्ष्मजीव मृदा की सरंध्रता और वायु संचरण को बढ़ाने में मदद करते हैं। उच्च कार्बन स्तर के साथ मिट्टी की नमी धारण करने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। इस प्रकार जल की बर्बादी को भी कम किया जा सकता है। सरल शब्दों में कहें, तो जैविक कार्बन स्तर का मृदा की उत्पादकता का संबंध टिकाऊ कृषि के साथ प्रत्यक्ष संबंध है तथा कृषि अवशेषों और बाह्य कार्बनिक पदार्थों-गोबर की खाद, वर्मीकम्पोस्ट आदि को मिलाकर जैविक कार्बन स्तर को बढ़ाया जा सकता है।

टिकाऊ खेती हेतु कार्ययोजना, उपयुक्त फसल चयन: पौधे, वायुमंडल से कार्बनडाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं तथा इसे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से आहार में परिवर्ति त करते हैं। आदर्श रूप से, ऐसी फसलें उर्गाइ जानी चाहिए, जिनका बायोमास अधिक हो और जो मृदा के कार्बनिक पदार्थ को बढ़ाकर दीर्घकालिक उत्पादकता में योगदान दें। आर्थिक लाभ के लिए किसान केवल उच्च और सुरक्षित आय देने वाली फसलों का उत्पादन करना चाहते हैं। भले ही यह लाभ अल्पकालिक हो। उच्च जैविक कार्बन और दीर्घ कालिक उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए फसल प्रारूप में परिवर्तन तब तक नहीं होगा, जब तक वांछित वैकल्पिक फसलें लाभदायक न हों।

बाहरी स्त्रोतों से कार्बनिक पदार्थ: गाय के गोबर, कम्पोस्ट आदि के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिये। मनरेगा और अन्य कार्यक्रमों से प्राप्त धन का उपयोग वर्मी कम्पोस्ट गड्ढों या 'नाडेप' खाद टैंकों के निर्माण को सब्सिडी देने के लिए किया जाना चाहिए। शहरी हरित अपशिष्ट और सीवेज उपचार संयंत्रों से बनी खाद को भी खेत की मृदा में स्थानांतरित किया जा सकता है। इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि जब नाइट्रोजन, फास्पफोरस और पोटेशियम की खुराक का उपयोग पारंपरिक खेत की खाद के साथ किया जाता है, तो अनुपात और जैविक कार्बन दोनों का स्तर बढ़ जाता है।

फसल चक्रीकरण: इस विधि में भूमि की उर्वराशक्ति बनाए रखने के लिए एक के बाद एक फसलें उगाई जाती हैं। इससे मृदा की उर्वरता बनी रहती है। खरीफ/रबी मौसम के दौरान चावल-गेहूं प्रणालियों में या ग्रीष्मकालीन फसल के रूप में दालें या फलीदार फसलों को उगाना आवश्यक है। इन फसलों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु होते हैं। ये वातावरण से नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं। नाइट्रोजन लंबे समय तक मृदा में कार्बन को स्थिर करने में मदद करता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस में दालों को शामिल करने से जनता के लिए पोषण सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। इसके साथ ही दालों के अधिक उत्पादन से मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलने से दूरगामी लाभ होगा।

शून्य जुताई को बढ़ावा: शून्य जुताई को बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता है। मृदा के बड़े टुकड़ों में जैविक कार्बन बरकरार रहता है। गहरी जुताई वाले उपकरण इन बड़े टुकड़ों को तोड़कर मृदा जैविक कार्बन को नुकसान पहुंचाते हैं।

फसल अवशेषों का उपयुक्त नियोजन: कर्टाइ के बाद पुआल और सूखे भूसे का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन किया जाना चाहिए। पुआल जलाने से पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के अलावा मृदा की उर्वरता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब फसल के अवशेष जलाए जाते हैं, तो वे मृदा मे ं मिल जाते हैं और मृदा में कार्बनिक कार्बन मिलाने की बजाय कार्बनडाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। हैप्पी सीडर, सुपर-स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम अटैचमेंट, मल्चर और चॉपर-शेडर जैसे उपकरणों पर सब्सिडी देकर इसके समाधन के प्रयास चल रहे हैं। टिकाऊ कृषि और बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए सभी राज्यों के सक्रिय सहयोग की आवश्यकता है।

टिकाऊ खेती और जलवायु परिवर्तन: वायुमंडलीय कार्बनडाइऑक्साइड को मृदा में पौधों के अवशेषों द्वारा और फसल उत्पादन के दौरान अवशोषित करने की प्रक्रिया के माध्यम से मृदा में कार्बनिक कार्बन के रूप में संग्रहित किया जाता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए कार्बन प्रच्छादन वास्तव में एक शक्तिशाली उपाय हो सकता है। पिछले चार वर्षों में केंद्र के मृदा स्वास्थ्य कार्ड कार्यक्रम से प्राप्त नमूनों के परीक्षण के परिणामों के आधार पर मृदा स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं है। देश के अधिकांश हिस्सों में जैविक कार्बन बहुत कम पाया गया है। समशीतोष्ण जलवायु में मृदा में कार्बन की मात्रा बेहतर होती है। यह भारत जैसे गर्म उष्णकटिबंधीय वायुमंडलीय क्षेत्रों के विपरीत है, जहां मृदा पौधों के मलबे के अपघटन, खनिजीकरण के माध्यम से कार्बन खो देती है। **साभार**

मक्का का बढ़ता व्यावसायिक महत्व

भारत में गेहूं और धान के बाद मक्का को महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसल के रूप में पहचान मिली हुई है। हाल के वर्षों में इसके-संस्करित खाद्य उत्पादों की मांग में भी कापफी बढ़ोतरी हुई है। इनमें इंस्टेंट तैयार होने वाले पैक्ड आहारों का विशेषतौर पर उल्लेख किया जा सकता है। अब इसका उपयोग देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने में भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। सरकार की ओर से मक्का का प्रयोग देश के ईंधन मिश्रण कार्यक्रम के अंतर्गत इथेनॉल बनाने के लिए किया जा रहा है। 'फार्म टू फ्यूल' नामक महत्वाकांक्षी योजना में सरकार की ओर से किसानों को मक्का उगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसी क्रम में कृषि वैज्ञानिकों से भी मक्का की अधिक उपज देने में सक्षम उन्नत किस्मों के विकास पर फोकस करने को कहा गया है। इसके अतिरिक्त कृषकों के बीच मक्का की खेती के प्रचार-प्रसार के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी देशव्यापी स्तर पर आयोजित करने की योजना पर अमल किया जा रहा है। सरकारी पोषण के अनुसार भारत का लक्ष्य आगामी पांच वर्षों में 10 मिलियन टन तक मक्का का उत्पादन बढ़ाने का है, क्योंकि इथेनॉल की मांग में निरंतर वृ(देखने को मिल रही है। इसके बाद मक्का की मांग पोल्ट्री उद्योग में भी लगातार बढ़ती हुई देखी जा सकती है। यह मुर्गियों के आहार के रूप में काफी उपयोगी माना जाता है। देश के खाद्यान्नों में यह तीसरी सर्वाधिक उत्पादित फसल है। वर्ष 2022-23 में 34.6 मिलियन टन मक्का होने का अनुमान जताया गया है, जबकि गत वर्ष यह 33.7 मिलियन टन था। सरकारी जैव ईंधन नीति के अनुसार आने वाले समय में गन्ने से इथेनॉल का उत्पादन कम करने तथा मक्का जैसे अनाज से उत्पादन करने पर जोर दिया जाएगा। देश में भाकृअनुप-भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक मक्का की उच्च उत्पादन देने में सक्षम बीजों को विकसित करने के लिए प्रयासरत हैं। गौरतलब है कि जैर्व ईंधन गन्ना, चावल और मक्का जैसे अनाजों से तैयार किया जाता है। वर्तमान में लगभग 25 प्रतिशत इथेनॉल गन्ने के रस से तैयार किया जाता है, जबकि 50 प्रतिशत गुड़ से बनाया जाता है। शेष 25 प्रतिशत इथेनॉल अनाज से ही निर्मित किया जाता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से मक्के को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की भी योजना पर कार्य किया जा रहा है। इस नई पहल से किसानों की आय बढ़ाने के साथ वर्ष 2025-26 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल का मिश्रण करने का लक्ष्य सुनिश्चित किया जा सकेगा। इससे देश के कच्चे तेल के आयात बिल में कापफी कमी आएगी और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत की जा सकेगी। किसान भाइयों को समय रहते इस योजना का लाभ उठाने के लिए मक्का के उत्पादन की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए तथा इसके व्यावसायिक महत्व का पफायदा उठाते हुए अपनी मेहनत की कमाई में पर्याप्त बढ़ोतरी करने पर ध्यान देना चाहिए। **साभार**

-कृषि वैज्ञानिक पता करेंगे कि खेत में कम क्यों हो रही उपज

मप्र-उप्र के पांच गांव गोद लेकर शुरू हुआ पायलट प्रोजेक्ट

भोपाल। जागत गांव हमार

बुंदेलखंड में उन्नत बीजों से भी किसानों को कम उपज मिलने की शिकायतें खूब सामने आती हैं. इसके समाधान के लिए झांसी स्थित केंद्रीय कृषि विवि ने 4 ने 5 गांवों को गोद लेकर किसानों के साथ मिलकर उन फसलों को उपजाने की पहल की है, जिनकी बेहतर उपज विश्वविद्यालय के फार्म में ली जाती रही है। इससे यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि कृषि विश्वविद्यालय के फार्म में वैज्ञानिक जिन विकसित बीज से जितनी उपज ले रहे हैं, उन्ही बीजों से किसान के खेत में कम उपज क्यों मिल रही है। ये जानने के लिए वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर खेती करेंगे. इसके साथ साथ विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक किसानों के साथ मिलकर उनके खेतों में ही आधुनिक खेती पर शोध भी करेंगे।

पांच गांव लिए गोद

रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विवि के कुलपति डॉ. अशोक कुमार सिंह की ओर से इस अनूठे प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया कि बीजों की उत्पादन क्षमता को लेकर शोध के परिणाम में किए गए दावों पर किसान यकीन नहीं कर पाते हैं। किसानों को लगता है कि जिन बीज से विवि की फार्म में जितनी उपज हो जाती है, उतनी उपज उनके खेत में वही बीज उपजाने पर क्यों नहीं होती है। किसानों के मन में वैज्ञानिकों के दावों को लेकर पनपे भ्रम को दूर करने के लिए वैज्ञानिक अब उनके खेतों पर ही अपने बीजों से उतनी ही उपज लेकर दिखाएंगे।

शिक्षित किसानों को जोड़ा गया

इस परियोजना में शामिल किए गए शिक्षित किसानों को जोड़ा गया है। इन किसानों के खेत पर वैज्ञानिक पद्धिति का प्रयोग कर मिट्टी से लेकर फसल तक, सभी मामलों में आधुनिक खेत के प्रयोग भी किए जाएंगे। जिससे किसान खेती में आधुनिक तकनीक से रूबरू हो सके। प्रोजेक्ट से जोड़े गए किसानों को मानदेय भी दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की कमान विवि के प्रसार शिक्षा निदेशक डॉ. एसएस सिंह को सौंपी गई है। इसका संयोजक डॉ. प्रशांत जांबुलकर और डॉ. आशीष गुप्ता को बनाया गया है। इसके तकनीकी विशेषज्ञ डॉ. डीवी सिंह होंगे।

शून्य प्रौद्योगिकी अंतराल प्रोजेक्ट

वैज्ञानिक खेतों में कोई अतिरिक्त तकनीकि इस्तेमाल नहीं करेंगे। वे किसानों को खेती के लिए सुझाई जा रही तकनीक अपना कर ही फसल उपजा कर दिखाएंगे। जिससे विवि के फार्म में अपनाई जा रही तकनीक को ही किसान भी आगे इस्तेमाल कर सकें। दोनों के बीच तकनीक के भेद को मिटाने के लिए इस परियोजना को शून्य प्रौद्योगिकी अंतराल प्रोजेक्ट नाम दिया गया है। इसके लिए बुंदेलखंड में यूपी और एमपी के 5 गांव गोद लिए गए हैं। इनमें यूपी के ललितपुर जिले में मीलिया, सिरौन और बम्होरी कला, झांसी जिले का मगरपुर और एमपी में निवाड़ी जिले का परजपुरा गांव शामिल है।

-नर्मदापुरम में लगभग 20 से 25 एकड़ फसल खराब

फफूंद ने चौपट कर दी फसल, दवा भी बेअसर कृषि वैज्ञानिक ने बताया गजब का आइडिया

नर्मदापुरम। जागत गांव हमार

जिले के सिवनी मालवा सहित शिवपुर तहसील के अधिकांश गांवों में चने की फसल पीली होने के साथ ही सूखने लगी है। लगभग 20 से 25 एकड़ फसल खराब हो चुकी है। खड़ी फसलों पर किसान अब ट्रैक्टर चलाकर खेत खाली करने लगे हैं। किसानों ने बताया कि इस साल बारिश होने से चने की फसल पीली पड़ी, फिर सूख गई। इसके चलते खासा नुकसान हुआ है। अब ट्रेक्टर चलाकर खेत को खाली कर रहे हैं। खाली करने के बाद अगली फसल के लिए खेतों को तैयार करेंगे।

फसल में फफूंद रोग- जिले के शिवपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम कुंडकला, हमीदपुर सहित अन्य ग्रामों में कृषि वैज्ञानिक केके मिश्रा ने कृषि विभाग के अधिकारियों एवं नायब तहसीलदार के साथ खेतों में पहुंचकर फसलों का निरीक्षण किया। बताया कि चने की फसल में फफूंद रोग भी दिखाई दे रहा है। फसल ग्रोथ नहीं कर पा रही। पौधे रूखे होकर सूख रहे हैं। अब इसमें दवा डालने का भी कोई लाभ नहीं होगा।

किसानों को सलाह

कृषि वैज्ञानिक ने बताया कि फसलों में मिट्टी जनक फफूंद लगे हुए हैं। पौधा आसानी से उखड़ जा रहा है। इसमें कोई दवा छिड़काव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे कोई सुधार नहीं होगा। अब किसान खेतों में गर्मी की जुताई करें, फिर उसमें हरी खाद डालें। जब वो लगभग 1 फिट की हो जाए उसके बाद मिट्टी को हल या प्लाऊ से पलट दें एवं पलटने के बाद उसमें पानी लगा दें। सड़ने के लिए छोड़ दें। पानी लगे खेत में ट्राइकोडर्मा का एप्लीकेशन करना है। उसे गोबर की खाद में मिला कर एक एकड़ में 3 किलोग्राम पर्याप्त होता है।

ये तीन का कर लें किसान

सिर्फ किसान ये 3 काम कर लें तो उसकी समस्या समाप्त हो जाएगी। पहले खेत में गर्मी की जुताई, दूसरी हरी खाद का प्रयोग एवं तीसरा ट्राइकोडर्मा एप्लीकेशन इससे मिट्टी में फफूंद की समस्या समाप्त हो जाएगी। नहीं तो ये बढ़ती जाएगी। मिट्टी के कीटाणु 3 से 4 साल तक बने रहते हैं।

जांच करने के लिए अब बड़े प्रयोगशाला में जाने की जरूरत नहीं होगी

सब्जियों-अनाजों में कीटनाशकों की मौजूदगी तुरंत चल जाएगी पता

भोपाल। जागत गांव हमार

साग-सब्जी और मिट्टी-पानी में मौजूद कीटनाशकों की जांच करने के लिए अब बड़े प्रयोगशाला में जाने की जरूरत नहीं होगी। रैपिड किट की मदद से अब इसकी जांच आसानी से की जा सकेगी। यह किट भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से प्रदेश के हर जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग को भेजी जा रही है। खाद्य पदार्थ के संपर्क में आते ही इस पीले रंग के सेंसर पेपर का रंग कीटनाशक की मात्रा के अनुसार बदल जाता है। हल्का लाल से गहरा लाल तक का रंग कीटनाशक की मौजूदगी बताता है। इस किट का सेट अब प्रदेशभर में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को जांच के लिए दिया जा रहा है। इससे सब्जी ही नहीं, अनाजों के सैंपल को भी अलग-अलग पद्धतियों से जांचा जा सकता है। अधिकारियों की मानें तो इस तरह की जांच के लिए करीब 250 रुपए तक का खर्च आएगा।

कैंसर के बढ़ रहे मरीज

जेपी अस्पताल के एमडी मेडिसिन डॉ. योगेंद्र श्रीवास्तव का कहना है कि कीटनाशकयुक्त सब्जियों और अनाज के माध्यम से ये कीटनाशक हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसकी वजह से आंखों में खुजली होना, मुंह में छाले पड़ना, बच्चों में उल्टी-दस्त की परेशानी होती है। माताएं यदि इस तरह की सब्जी का इस्तेमाल करती हैं तो यह दूध के जरिए बच्चों तक पहुंच जाता है। यह आने वाले समय में कैंसर का रूप भी ले लेता है।

प्रदेश में सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के लिए रैपिड किट आ रही है। इस किट से सब्जियों और अनाजों में कीटनाशकों की मौजूगी का पता तुरंत लगाया जा सकेगा। अब इस किट से सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारी जांच करेंगे।
- देवेंद्र दुबे, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, भोपाल

कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा पशु स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन

पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य से मिलता है अच्छा उत्पादन: डॉ. सिंह

लहर (भिंड)। जातम गांव हमार

कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा निकरा परियोजना अंतर्गत चयनित गांव गिरवासा में पशु स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर गांव के पशुपालकों के गाय-भैंस और उनके बच्चों हेतु दवाएं एवं खनिज लवण मिश्रण का वितरण किया गया। साथ ही गांव की बकरियां में पीपीआर की वैक्सीन का टीकाकरण भी किया गया। शिविर के दौरान वैज्ञानिकों एवं पशु चिकित्सकों की टीम द्वारा गांव के पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण के साथ मौके पर ही पशुओं की समस्याओं का भी निदान किया गया। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ एसपी सिंह ने पशुपालकों को संबोधित करते हुए कहा कि समय-समय पर सभी छोटे बड़े पशुओं की स्वास्थ्य की जांच कराया जाना बहुत आवश्यक होता है।

पशुओं का स्वास्थ्य बेहतर बनाकर उनसे अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि गांव के अधिकांश डेयरी पशुओं के सभी छोटे-बड़े गाय-भैंस उनके बच्चों में स्वास्थ्य खराब होने की प्रमुख वजह पेट में पाए जाने वाले अंतः तथा शरीर के ऊपर पाए जाने वाले वाह्य: परजीवी होते हैं। अत: इनका उचित समय पर निदान किया जाना नितांत आवश्यक होता है।

ये रहे मौजूद

शिविर में प्रमुख रूप से कृषि विज्ञान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ एसपी सिंह, वैज्ञानिक डॉ. एनएस भदोरिया, एसआरएफ दीपेंद्र शर्मा, पशुपालन विभाग की एवीएफओ अंजना चौधरी, गौ सेवक दिनेश जोशी द्वारा शिविर में पशुपालकों को जानकारी देने के साथ ही दवा आदि का वितरण किया गया।
शिविर में गांव के कृषक विनोद दुबे एवं कप्तान सिंह यादव का सहयोग सराहनीय रहा।

दवा के साथ ही खनिज लवण मिश्रण का निःशुल्क वितरित

शिविर के दौरान गांव के अधिकांश छोटे-बड़े डेरी पशुओं के पेट में कीड़ों की समस्या तथा दुधारू गाय-भैंस में बांझपन के साथ ही समय पर गर्भाधारण न करने की समस्या पाई गई। जिसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा मौके पर ही पशुपालकों को भिनाशक दवा के साथ ही खनिज लवण मिश्रण का निःशुल्क वितरित किया गया। वही पशुपालन विभाग द्वारा गांव की बकरियां को बकरी प्लेग रोग से बचाव के लिए पीपीआर की वैक्सीन का टीका लगाया गया। शिविर में गांव के 64 पशुपालकों के 276 से अधिक छोटे-बड़े डेरी पशुओं को भिनाशक दवा, खनिज लवण मिश्रण आदि प्रदान किया गया।

दुनिया के कई हिस्सों में मधुमक्खियों की आबादी घट रही

2032 तक मधुमक्खी पालन बाजार 15.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंचने का लक्ष्य

प्राकृतिक मिठास के लिए उपभोक्ता मांग बढ़ रही

भोपाल/नई दिल्ली। जागत गांव हमार

मधुमक्खियां फसलों को परागित करके कृषि और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, फिर भी दुनिया के कई हिस्सों में मधुमक्खियों की आबादी घट रही है। इससे मधुमक्खी पालन - मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन - में गहरी रुचि पैदा हो रही है। वास्तव में, वैश्विक मधुमक्खी पालन बाजार का आकार 2022 में 10.3 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2032 तक 15.3 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो इस अवधि के दौरान 4ब्न की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है। शहद के उपयोग को बढ़ावा: मधुमक्खी पालन में रॉयल जेली, मधुमक्खी पराग, प्रोपोलिस और शहद जैसे विभिन्न उत्पादों की कटाई के लिए मधुमक्खी कॉलोनी का रखरखाव शामिल है, जो व्यापक रूप से उद्योगों में उपयोग किया जाता है। बढ़ती उपभोक्ता जागरूकता उच्च वैश्विक प्रति व्यक्ति खपत वाले उत्पाद, विशेष रूप से शहद के उपयोग को बढ़ावा देती है। शहद का औषधीय उपयोग आहार संबंधी आदतों को प्रभावित करता है, और मधुमक्खी पालन के उपोत्पादों का उपयोग फार्मास्यूटिकल्स, साबुन और सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है। बढ़ती मांग, विशेष रूप से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया प्रशांत में, वाणिज्यिक मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देती है। संगठनों का समर्थन जैविक कृषि को बढ़ावा देता है, जिससे जैविक शहद बाजार को बढ़ावा मिलता है।

विश्व में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा: शहद और अन्य मधुमक्खी उत्पादों के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना-प्राकृतिक मिठास के लिए उपभोक्ता मांग बढ़ रही है और कच्चे शहद, प्रोपोलिस, रॉयल जेली, मोम और मधुमक्खी पराग के स्वास्थ्य और औषधीय लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ रही है। अनुसंधान एंटीऑक्सीडेंट, विरोधी भड़काऊ और रोगाणुरोधी गुणों को इंगित करता है। इन मधुमक्खी उत्पादों की लोकप्रियता मधुमक्खी पालन बाजार के विस्तार को प्रेरित कर रही है। व्यक्तिगत देखभाल उद्योगों में वृद्धि: शहद, प्रोपोलिस और रॉयल जेली जैसी मधुमक्खी सामग्री का उपयोग पोषण संबंधी पूरकों के साथ-साथ त्वचा क्रीम, साबुन, शैंपू और लिप बाम जैसे व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों में तेजी से किया जा रहा है। इन उद्योगों में बड़े खिलाड़ी मधुमक्खी उत्पादों को नई पेशकशों में एकीकृत करने में बहुत रुचि दिखा रहे हैं।

मधुमक्खी पालन के प्रयासों में वृद्धि

कॉलोनी पतन विकार और आवासों के नुकसान के कारण मधुमक्खियों की आबादी में गिरावट आई है। सरकारी पर्यावरण संरक्षण प्रयासों में अक्सर परागणकों की सुरक्षा के उपाय शामिल होते हैं। कॉलोनी के नुकसान का मुकाबला करने और शहद उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए मधुमक्खी पालन और पेशेवर मधुमक्खी पालन का शौक भी बढ़ रहा है। नए खिलाड़ी मधुमक्खी पालन उद्योग में प्रवेश कर रहे हैं, छोटे पिछवाड़े के मधुमक्खी पालकों से लेकर बड़े वाणिज्यिक संचालन तक।

मधुमक्खी पालन स्वचालन प्रौद्योगिकियों में प्रगति

कई स्टार्टअप और स्थापित निर्माता वाणिज्यिक पैमाने पर मधुमक्खी पालन को अधिक कुशल, उत्पादक और कम श्रम-गहन बनाने के लिए नए स्वचालित छत्ता निगरानी समाधान, सटीक फीडिंग तकनीक, एकीकृत सेंसर, एआई और मोबाइल ऐप विकसित कर रहे हैं। इन क्षेत्रों में निवेशकों की फंडिंग और अनुसंधान एवं विकास बढ़ रहा है। बाज़ार के लिए तैयार प्रौद्योगिकियों के साथ-साथ नवप्रवर्तक उद्योग के विकास को प्रभावित करेंगे।

मधुमक्खी के डंक से एलर्जी की बढ़ती घटनाएं

जबकि अधिकांश मधुमक्खी के डंक से मामूली प्रतिक्रियाएं होती हैं, कुछ लोग गंभीर, संभावित रूप से घातक एलर्जी प्रतिक्रियाओं से पीड़ित हो सकते हैं। मधुमक्खी के जहर या शहद की एलर्जी के निदान और उचित उपचार के लिए एलर्जी परीक्षण, जहर इम्यूनोथेरेपी और आपातकालीन एपिनेफ्रिन इंजेक्शन की आवश्यकता होती है। मधुमक्खी के डंक से होने वाली एलर्जी से स्वास्थ्य देखभाल का बोझ बढ़ रहा है, जो अप्रत्यक्ष रूप से अनुसंधान संस्थानों और एलर्जी दवाओं और उपचारों के निर्माताओं की ओर से मधुमक्खी पालन क्षेत्र में खर्च को बढ़ाता है। प्राकृतिक परागणकों में गिरावट के कारण फसल परागण के लिए प्रबंधित मधुमक्खी कालोनियों पर निर्भरता बढ़ गई है। इस संकट ने मधुमक्खी पालन उत्पादों और सेवाओं की बढ़ती मांग को बढ़ावा दिया है, जिससे बाजार के विस्तार का एक अनूठा अवसर पैदा हुआ है।

मधुमक्खी पालन बाज़ार के अवसर

मधुमक्खी पालन बाजार केवल शहद की कटाई के बारे में नहीं है, यह विभिन्न उद्योगों में अवसरों का एक समूह प्रस्तुत करता है। जैसे-जैसे मधुमक्खी पालन उत्पादों के बारे में उपभोक्ता जागरूकता बढ़ रही है, रॉयल जेली, मधुमक्खी पराग और अन्य डेरिवेटिव की मांग में समानांतर वृद्धि देखी जा रही है। वाणिज्यिक मधुमक्खी पालन, विशेष रूप से कॉस्मेटिक और औषधीय क्षेत्रों की बढ़ती मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। मधुमक्खी पालन से जुड़ी लागत-प्रभावशीलता और कम रखरखाव इसे एक आकर्षक उद्यम बनाता है, जो उद्योग के विकास को और बढ़ावा देता है।

बढ़ती जागरूकता: जैसे-जैसे उपभोक्ता पर्यावरण के प्रति अधिक जागरूक होते जा रहे हैं, टिकाऊ प्रथाओं का समर्थन करने की दिशा में उल्लेखनीय बदलाव आ रहा है। मधुमक्खी पालन, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य पर अपने सकारात्मक प्रभाव के साथ, इस प्रवृत्ति से लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है।

छत्ता प्रौद्योगिकी में नवाचार: मधुमक्खी पालन प्रथाओं में स्मार्ट छत्ता और डेटा एनालिटिक्स जैसी प्रौद्योगिकी का एकीकरण दक्षता और उत्पादकता को बढ़ा रहा है। ये नवाचार न केवल तकनीक-प्रेमी मधुमक्खी पालकों को आकर्षित करते हैं बल्कि बाजार के विकास के नए रास्ते भी खोलते हैं।

प्रतिस्पर्धी परिदृश्य: मधुमक्खी पालन बाजार के प्रतिस्पर्धी परिदृश्य को प्रमुख खिलाड़ियों द्वारा नए विकास के अवसर उत्पन्न करने के लिए विभिन्न रणनीतियों को नियोजित करने द्वारा चिह्नित किया गया है। अधिग्रहण, सहयोग, नए उत्पाद लॉन्च, पोर्टफोलियो विस्तार, साझेदारी और समझौते उद्योग में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखने के लिए इन खिलाड़ियों द्वारा अपनाई गई प्रमुख रणनीतियों में से हैं।

मीठा बांस बढ़ाएगा किसानों की आय

भोपाल। जागत गांव हमार

गहन शोध के बाद शोधकर्ताओं ने प्रयोगशाला में मीठे बांस की एक विशेष प्रजाति को तैयार करने में सफलता हासिल कर ली है। यह शोध बिहार के जिला भागलपुर में टीएनबी कॉलेज स्थित प्लांट टिश्यू कल्चर लैब, पीटीसीएलद्ध में किया गया। यहां मीठे बांस के पौधे व्यावसायिक दृष्टि से वृहद स्तर पर तैयार किये जा रहे हैं।

किसान इस व्यवसाय को अपनाकर अपनी आय को दोगुना कर सकेंगे। अब इससे ग्रामीण आर्थिकी को समृ करने के लिए नई संभावनाओं का आगमन होगा। बांस की खेती बिहार की अर्थव्यवस्था को बदलने में पूरी तरह सक्षम हो सकती है, क्योंकि वर्तमान समय में इस बांस की मांग अधिक है। आज विश्व में कई देशों में इससे खाद्य उत्पाद भी बनाए जाते हैं। इसके साथ ही इस प्रजाति का उपयोग दवाइयां बनाने में भी किया जा रहा है।

सभी मौसम व मृदा में होगी खेती

बांस की इस प्रजाति की खेती किसी भी मौसम व सभी प्रकार की मृदा में की जा सकेगी। परीक्षण के दौरान एनटीपीसी से निकले राख के ढेर पर भी इसके पौधे उगाने में शोधकर्ताओं को सफलता हासिल हुई है।

खाद्य उत्पादों में भी उपयोगी

खाद्य प्रसंस्करण इकाई के माध्यम से बांस के इन पौधों से विभिन्न प्रकार के खाद्य उत्पाद तैयार किये जा सकेंगे। इनका उपयोग चीन, ताईवान, सिंगापुर, पिफलीपींस आदि देशों में बड़े स्तर पर चिप्स, अचार, कटलेट जैसे उत्पाद तैयार करने में किया जाता है। अब भारत में भी इसका उपयोग व्यावसायिक तौर पर हो सकेगा। इससे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को कापफी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही इन पौधों से एंटीऑक्सीडेंट और कैंसर जैसे रोगों की दवाइयां भी बनाई जा सकेंगी। बांस के पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अच्छी तरह से अवशोषित कर कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। ये पदार्थ मृदा में मिलकर, मृदा की उर्वराशक्ति भी बढ़ाते हैं। बांस की सहायता से बायो एथेनॉल, बायो सीएनजी एवं बायोगैस उत्पादन पर भी शोध प्रगति पर है। भारत में बांस की 135 से अधिक व्यावसायिक प्रजातियां पाई जाती है।

फसलों को नुकसान पहुंचाने के कारण विभाग की तैयारी

मध्यप्रदेश में ब्लैक बक और नीलगाय को हेलीकॉप्टर के जरिए किया जाएगा शिफ्ट

भोपाल। जागत गांव हमार

प्रदेश के कई जिलों में किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे ब्लेक बक एवं नीलगाय को अन्यत्र शिफ्ट करने की योजना राज्य के वन विभाग ने बनाई है। इसके लिये वन्यप्राणी शाखा ने बजट उपलब्ध कराने की राज्य शासन से मांग की है। दरअसल, पहले योजना बनाई गई थी कि फसलों को हानि से बचाने के लिये उक्त वन्यप्राणियों का बन्दूक से शिकार करने के नियम सरल किये जायें। लेकिन इसमें अड़चन आने पर अब निर्णय किया गया है कि जहां-जहां ये वन्यप्राणी फसलों को हानि पहुंचा रहे हैं, उन्हें वहां से हटाकर अन्यत्र स्थानांतरित किया जाए। वन्यप्राणी विशेषज्ञ भी लंबे समय से यहीर सलाह दे रहे थे। वन्यप्राणी शाखा ने प्रदेश के शाजापुर जिले एवं अन्य उपयुक्त स्थानों से 100 नीलगाय एवं 400 ब्लैक बक के अन्यत्र स्थानांतरण की योजना बनाई जिसके लिये राज्य शासन ने 100 नीलगायों के स्थानांतरण पर अपनी स्वीकृति दे दी है तथा केंद्र से भी अनुसूची एक में शामिल ब्लेक बक के स्थानांतरण की मंजूरी मांगी गई है। केंद्र से मंजूरी मिलने पर संबंधित वनमंडलों के डीएफओ से प्रस्ताव आने पर इन्हें अन्यत्र स्थानांतरित करने की स्वीकृति दी जायेगी और बजट भी उपलब्ध कराया जाएगा।

दक्षिण अफ्रीका के विशेषज्ञों का सुझाव

नीलगायों एवं ब्लेक बक का शाजापुर एवं उसके पास के जिलों से बोमा बनाकर हेलीकाप्टर द्वारा स्थानांतरण किया जाएगा। इसके लिए दक्षिण अफ्रीका से आए वन्यप्राणी विशेषज्ञों ने भी सुझाव दिया है। वन विहार से भी कई बार इसी पैटर्न पर वन्यप्राणी शिफ्ट किए जा चुके हैं।

राजस्व विभाग देता है मुआवजा

इधर, वन मुख्यालय से वन्यप्राणियों द्वारा किसानों की फसलों को हानि पहुंचाने पर वन विभाग के अंतर्गत ही मुआवजा देने का प्रस्ताव आया था, लेकिन राज्य शासन स्तर पर इसमें टीप दी गई है कि फसल हानि का मुआवजा राजस्व विभाग द्वारा दिया जाता है। वहीं से इसका निराकरण होगा, वन विभाग अपने यहां ऐसा प्रावधान नहीं कर सकता है।

-कम समय में होगा अधिक से अधिक मुनाफा

फरवरी में किसान शुरू करें भिंडी की खेती

फरवरी का महीना शुरू होते ही भिंडी बोने की तैयारी करनी चाहिए। फरवरी में सर्दी के तेवर ढीले पड़ने लगते हैं। साल का यह दूसरा महीना भिंडी की फसल की बोवनी के लिए मुफीद होता है। अगर इसकी खेती का इरादा हो और भिंडी से लाखों का मुनाफा चाहते हैं तो आपको इसकी अगेती फसल करनी चाहिए। कई बार किसान फसल लगाने में लेट हो जाते हैं और मंडी में भी लेट पहुचती है, जिससे सही रेट नहीं मिलता है। इसलिए हमें हमेशा अगेती खेती ही करना चाहिए। तो इसकी बोवनी निपटा लेनी चाहिए। भिड़ी के अंकुरण के लिए फरवरी का महीना बेहतर रहता है। गर्मियों में भिंडी की मांग ज्यादा रहती है। हालांकि, बोवनी के लिए सही किस्म की भिंडी का चयन जरूरी है।

भोपाल। जागत गांव हमार

बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को सब्जी विज्ञान बिभाग के प्रो. डॉ. अजीत सिंह के मुताबिक भिंडी की बुवाई के लिए एक बार गहरी जुताई करने के बाद दो बार कल्टीवेटर से हल्की जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी कर लें। मिट्टी को भुरभुरा करने के बाद अगर आपने मिट्टी की जांच कराई है। जिन खाद उर्वरकों जिस चीज के जरूरी बताई गई है। उसी खाद या पोषक तत्वों का प्रयोग करें। अगर आप किसी वजह से अपने खेत की मिट्टी की जांच नहीं करवा पाए हैं तो इसमें 90 किलो यूरिया और 50 डीएपी और 30 किलो एमओपी की प्रति एकड़ के हिसाब से भिंडी की खेती में प्रयोग में लाना चाहिए। इसमें से आधा भाग यूरिया और पूरा भाग डीएपी और पूरा भाग एमओपी का खेत की जुताई के समय ही खेत में देना पड़ेगा तथा बाकी बची हुई यूरिया को खड़ी फसल में इस्तेमाल किया जाता है।

अच्छी उपज के लिए सही बीज का चुनाव

डॉ. अजीत सिंह के अनुसार भिंडी की फसल की बोवनी के लिए अच्छी किस्मों का चुनाव करना चाहिए। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी से विकसित और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा दिल्ली की विकसित कई किस्में हैं। इसके आलावा कई बीज की प्राइवेट कंपनियां भी उन्नत और संकर भिंडी की बीज बेचती हैं। उसकी खरीदारी कर खेतों में लगा सकते हैं। वह बीज उन्नत किस्म का तथा उपचारित होने चाहिए। जायद भिंडी के बीजों को बोने से पहले 12-24 घंटे तक पानी में भिगोने से अंकुरण अच्छा होता है। बोवनी से पहले भिंडी के बीज को 3 ग्राम थीरम या कार्बेन्डाजिम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। उन्नतशील बीज 6 किलों संकर किस्मों के लिए 2 किग्रा। प्रति एकड़ बीज दर पर्याप्त होता है।

भिंडी की बोवनी का सही तरीका

सब्जी विज्ञान के विशेषज्ञ के मुताबिक भिंडी की बोवनी करते समय ध्यान रखना चाहिए कि इसकी बोवनी सीधी लाइन में ही करनी चाहिए। आज कल एक और ट्रेंड चल रहा है की उठी हुई क्यारियों में इसकी बोवनी की जाती है। इसमें कम से कम 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची बेड बनाकर इसकी बोवनी करनी चाहिए। इसके कई फायदे होते हैं जैसे पोषक तत्वों की उचित मात्रा पौधों को मिलती रहती है। जायद और गर्मी वाली भिंडी की बोवनी के लिए लाइन से लाइन की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए तथा पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखी जानी चाहिए।

बोवनी से पहले करें सिंचाई

डॉ. अजीत सिंह ने बताया कि बोवनी के बाद बारी आती है। सिंचाई व्यवस्था की अगर खेत में नमी ना हो तो बोवनी के पहले एक सिंचाई करनी चाहिए। इसके बाद 8 से 10 दिन के बाद सिंचाई की जरूरत होती है। सिंचाई के लिए फव्वारे या ड्रिप का प्रयोग करें जिससे पानी की भी बचत होगी और पौधों को पर्याप्त मात्रा में सिंचाई मिलती है। ड्रिप का प्रयोग करने से लगभग 80 फीसदी पानी की बचत होती है और घुलनशील पोषक तत्वों भी ड्रिप के जरिए दिए जा सकते हैं।

कम समय में अधिक मुनाफा

भिंडी की फसल 45 दिन में तोड़ने के लिए तैयार होने लग जाती है। जब भिंडी का साइज 4 से 5 इंच का बनने लग जाए और उनका रंग बिल्कुल हरा हो तो तुड़ाई करनी चाहिए। तुड़ाई करने के बाद भिंडी को अलग-अलग केटेगरी बनाकर बाजार में बेचना चाहिए, जिससे दाम भी उचित मिल सकें। अधिकांश सब्जी किसान कम लागत में इस समय भिंडी की फसल उगाकर लाखों रुपए कमाते हैं। इन बातों को ध्यान रख आप भी इसकी खेती कर बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं।

कीटनाशक के लिए पानी की सही मात्रा

जब हमारी फसल बढ़ रही होती है तो विशेष रूप से कीड़े और पतंगों का प्रकोप होता है अगर हमने सहनशील वैरायटी प्रयोग में ली है जिसमें बीमारियों का प्रकोप कम होता है तो ज्यादा उपचार की जरूरत नहीं पड़ती है। बीमारियों को फैलाने वाली सफेद मक्खी को काबू करने के लिए किसी भी एक कीटनाशक का प्रयोग जरूरी हो जाता है। किसानों को चाहिए कि जो हमेशी कोशिश करे नीम पर आधारित कीटनाशी प्रयोग ज्यादा करना चाहिए। इससे भिंडी का प्रयोग करने वाले उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य का नुकसान ना हो। इसमें आप 3 से 5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर के साथ घोल बनाकर उसका छिड़काव करें छिड़काव के वक्त विशेष ध्यान रखना चाहिए। छिड़काव हमेशा शाम के वक्त करें।

-सिर्फ शुद्ध घी से ही बनता है भंडारा

भिंड के एक गांव में पशुपालक नहीं बेचते दूध पूर्वजों के बताए रास्ते पर चल रहे ग्रामीण

तेल और रिफाइंड ऑइल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता

भिंड। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश के भिंड जिले के अटेर विधानसभा क्षेत्र के एक गांव से अजीबो गरीब मामला सामने निकल कर आया है। कमई गांव के लोगों ने दावा किया है कि पूरे गांव में दूध नहीं बेचा जाता है। जब इस मामले की पड़ताल की गई तो स्थानीय लोगों ने बताया कि हमारे गांव में कई पीढ़ियों से कोई भी ग्रामीण दूध नहीं बेचता है। आज के वक्त में लोग पशुपालन करते हैं और उनसे मिलने वाले दूध को वह महंगे दामों में बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन यहां के लोगों ने जो आपबीती सुनाया वो हैरान करने वाला था। गांव के लोगों ने बताया कि हमारे पूर्वजों के द्वारा बताया गया है कि जब कोई भी पशु गांव में लाया जाता है और वह दूध देता है तो सबसे पहले उस पशु के दूध को श्री हरसुख बाब के थान पर पहुंच कर दूध से बने व्यंजन का भोग लगाया जाता है। लोगों ने बताया कि हमारे गांव में हरसुख बाबा का सिद्ध स्थान है जहां से ग्रामीणों की अपार अस्था जुड़ी हुई हैं। गांव के लोगों का कहना है कि हम अपने पूर्वजों के बताएं रास्ते पर आज भी चल रहे हैं। गांव में दूध नहीं बेचते हैं। अगर गांव का कोई व्यक्ती अर्थिक रूप से कमजोर होता है तो वह दुध की जगह घी, पनीर, मावा आदि बेचकर पशुधन कमाते हैं।

शुद्ध घी से भंडारा

कमई में रहने वाले सोनू यादव ने बताया कि हमारे गांव में हरसुख बाबा के सिद्ध स्थान पर गांव के लोगों की ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र के लोगों की भी आस्था जुड़ी हुई है। गांव में हर साल विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों लोग प्रसादी ग्रहण करते हैं। इस भंडारे की खास बात यह है कि सब्जी, पूडी,खीर,मालपुआ सभी यहां शुद्ध घी से ही बनाए जाते हैं। तेल और रिफाइंड ऑइल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है।

गांव में ऐसे कई उदाहरण

गांव के बुजुर्ग रामप्रकाश राठौर ने बताया कि हमारे गांव में हर पशुपालक दूध न बेचते हुए दूध से घी, क्रीम, पनीर, मावा तैयार करके उसका सेवन कर उसे ही बेचते हैं। कमई निवासी प्रशांत यादव ने बताया कि गांव में ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जिन्होंने चोरी छिपे दूध बेचा तो उनकी भैंस या तो दूध देना ही बंद कर देती है या फिर वह बीमार पड़ जाती है। यह गांव जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित है। इस गांव में 200 घर हैं और आबादी 1100 के करीब बताई गई है।

दूध नहीं बेचने की मान्यता

ग्रामीणों ने बताया कि हमारे गांव में दूध नहीं बेचने की मान्यता है जिस कारण लोग दूध पीते हैं और बचे हुए दूध से घी बनाकर शुद्ध घी का सेवन करते हैं। इस कारण हर घर में शुद्ध घी रहता है। आवश्यकता से ज्यादा हो जाने पर उसे बेच भी देते हैं। लोग दूध दराज से इस गांव में शुद्ध घी खरीदने के लिए भी आते हैं। गांव में जब हरसुख बाबा के स्थान पर भंडारा होता है तो गांव के अधिकांश लोग अपने-अपने घरों से शुद्ध घी ,दूध ,मट्ठा, दही भंडारे में देकर अपना सहयोग प्रदान करते हैं। इस गांव में ज्यादातर यादव समाज के लोग निवास करते हैं और वह कहते हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं, इसलिए हम शुद्ध दूध, घी, पनीर, मावा का सेवन करके अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं।

-पुराने तालाबों और जल स्रोतों का होगा संरक्षण

-अतिक्रमण को हटाकर पौधारोपण भी करेंगे

प्रदेश में सरकार चलाएगी अब 'जल-हठ' अभियान

भोपाल। जागत गांव हमार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश के प्रत्येक ग्राम में हर घर तक जल पहुंचाने के लिए वर्ष 2019 में जल जीवन मिशन शुरू किया गया था। इस मिशन की पूर्ण सफलता के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में जल-हठ अभियान जन आंदोलन के रूप में चलाया जाएगा। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि इसमें सरकार और समाज की भागीदारी से हर गांव, हर नगर में पुराने तालाबों और अन्य जल स्रोतों का उन्नयन, विकास, सुंदरीकरण और गहरीकरण कराया जाएगा। जल स्रोतों के आसपास किए गए अतिक्रमण को हटाकर पौधारोपण किया जाएगा।

मंत्री मंत्री को दिया प्रस्ताव- तुलसी सिलावट ने इस संबंध में विभागीय प्रस्ताव पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल को सौंपा और अनुरोध किया कि प्रदेश के प्रत्येक ग्राम में जल-हठ अभियान को जन आंदोलन के रूप में चलाया जाए। पटेल ने आश्वस्त किया कि प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में जल स्रोतों के संरक्षण एवं जल संवर्धन को जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा।

जल स्रोत होंगे अतिक्रमण मुक्त

अभियान के अंतर्गत जल स्रोतों के अतिक्रमणों को प्राथमिकता से हटाया जाएगा। प्रदेश के तालाबों एवं अन्य जल स्रोतों में अतिक्रमण से उनका कैचमेंट क्षेत्र समाप्त होता जा रहा है, जिससे जल स्रोतों में प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। इससे सिंचाई और पीने का पानी कम हो रहा है।

मिलेगा पुनर्जीवन

ग्रामीण क्षेत्र के छोटे-छोटे नदी नालों में पहले वर्ष भर जल संरक्षित रहता था, ये नदी नाले अब लगभग समाप्त हो गए हैं। अभियान के अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों में प्राकृतिक जल स्रोतों, तालाबों के पुनर्जीवन कार्य के लिए उन्हें चिह्नित कर विभागीय योजना बनाई जाएगी। समाज के विभिन्न वर्गों एवं स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से इसे जन आंदोलन के रूप में चलाया जाएगा। अभियान में सभी जनप्रतिनिधियों, सामाजिक/ सांस्कृतिक संगठनों, खेल संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थानों, संत महंतों तथा बुद्धिजीवी वर्ग का भी पूरा सहयोग लिया जाएगा।

महंगा हुआ लहसुन तो किसानों ने खेतों में लगाए कैमरे, घर से भी रख रहे अपनी फसल पर नजर

भोपाल। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में लहसुन उत्पादक किसान बेहद खुश हैं, क्योंकि किसानों का लहसुन खेतों से ही 300 रुपए किलो के हिसाब से जगह पर ही थोक व्यापारी खरीद रहे हैं। और यही लहसुन बाजार में 400 रुपए किलो बाजार में बिक रहा है। इस बार किसानों को लहसुन से करोड़ो रुपए का फायदा हो रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि लहसुन की फसल की देखरेख के लिए खेतो में किसानों ने सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं। नजर रखी जा रही है कि लहसुन की कोई चोरी तो नहीं कर रहा। जिले के सांवरी गांव पोनार निवासी युवा किसान राहुल देशमुख आधुनिक खेती करते हैं। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से खेती कर करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाया है। उन्होंने पहली बार अपने खेतों में लहसुन लगाया है और उसकी देखरेख के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं।

सीसीटीवी कैमरे पर नजर रखता किसान

युवा किसान राहुल का कहना है कि सीसीटीवी के माध्यम से मजदूर काम करते दिखाई देते हैं। लहसुन महंगा है। चोरी का डर है, इसलिए भी कैमरे लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि आजकल तो सोलर वाला सीसीटीवी कैमरा आ गया है। इसमें बिजली की भी जरूरत नही होती। किसान राहुल ने बताया, मेरे खेत में पहले चोरी भी हुई थी, उसके बाद कैमरे लगाए गए। मैंने 13 एकड़ में लहसुन की फसल लगाई। फायदा 1 करोड़ से ऊपर है और 25 लाख रुपए की लागत लगी है। लहसुन बिकने के लिए हैदराबाद जा रहा है।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, **संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)